



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2016/भाद्र 30, 1938

No. 299]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016/BHADRA 30, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

**विषय :** चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ओ-एसिड के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

**संख्या 14/31/2016-डीजीएडी.** —मै. आरती ड्रग्स लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ओ-एसिड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

**घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

3. यह याचिका विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादक के रूप में, मै. आरती ड्रग्स लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य ज्ञात उत्पादक नहीं है। याचिकाकर्ता भारत में विचाराधीन उत्पाद का एक नया उत्पादक है जिसका भारत में उत्पादन का कोई पूर्व इतिहास नहीं है।

4. याचिकाकर्ता ने बताया है कि वे अंतिम उत्पाद अर्थात् आफलोक्सिन के उत्पादन में खपत के लिए ओ-एसिड का उत्पादन शुरू करने से पहले ओ-एसिड का आयात कर रहे थे। ओ-एसिड का अपना स्वयं का उत्पादन शुरू करने के बाद याचिकाकर्ता ने ओ-एसिड को आयात करना पूर्णतः बंद कर दिया था। तथापि चीन से निर्यातक ने अपनी कीमतों काफ़ी कम कर दी हैं। चीन के उत्पादकों द्वारा कीमतों में गिरावट इतनी अधिक है कि आयातित ओ-एसिड की पंहुच कीमत याचिकाकर्ता की मानित उत्पादन लागत से कम थी और इसलिए घरेलू उद्योग को अंतिम उत्पाद ओफलोक्सिन का उत्पादन जारी रखने के लिए चीन से ओ-एसिड का आयात करने को बाध्य होना पड़ा था।

5. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक का उत्पादन घरेलू उत्पादन का समान वस्तु के सकल घरेलू उत्पादन में 'प्रमुख हिस्सा' बनता है। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

### **विचाराधीन उत्पाद**

6. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद ओफलोक्सिन एसिड या ओ-एसिड है। यह एक आफ वाइट से वाइट क्रिस्टलीय पाउडर होता है और उसका प्रयोग ओफलोक्सिन के विनिर्माण के लिए मध्यवर्ती वस्तु के रूप में किया जाता है, जो एक फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग क्लास के कृत्रिम कीमोथेराप्युटिक एंटीबायोटिक है जिसे दूसरी पीढ़ी का फ्लोरोक्विनोलोन माना जाता है। ओफलोक्सिन एक रेसमिक मिश्रण होता है जिसमें 50 प्रतिशत लिवोफ्लोक्सिन (जैविक सक्रिय संघटक) और 50 प्रतिशत उसका 'मिरर इमेज' या इनेसेमर डेक्स्ट्राफ्लोक्सिन होता है।

7. ओफलोक्सिन एसिड का प्रयोग ओफलोक्सिन के उत्पादन में होता है जिसका प्रयोग ब्रोंसिटिस, निमोनिया सहित कतिपय संक्रमणों और त्वचा, ब्लेडर, यूरिनरी ट्रेक्ट, प्रजनन अंगों और प्रोस्टेट के संक्रमणों का उपचार करने में किया जाता है। ओफलोक्सिन को व्यापक प्रकार के ब्रांड नामों तथा जेनेरिक औषध समतुल्यों के अधीन ओरल और इंटराविनस खपत के लिए बेचा जाता है। ओफलोक्सिन आखों के ड्राप और कान के ड्राप के रूप में टॉपिकल प्रयोग के लिए भी उपलब्ध है। यह मूल स्वास्थ्य प्रणाली में जरूरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण दवाइयों अनिवार्य दवाइयों की डब्ल्यूएचओ माडल सूची में है। पीयूसी को आईपी/बीपी/ईपी/यूएसपी फार्माकोपिया मानक के अनुसार विनिर्मित किया जा सकता है।

8. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद पर जॉच की प्रस्तावित अवधि के लिए 5 प्रतिशत की दर से सीमाशुल्क लागू है। पीयूसी का विशिष्ट एचएस कोड 2941 9030 है तथापि आयात विभिन्न अन्य एचएस कोडों अर्थात् 2915 2990, 2916 3990, 2918 3090, 2918 9900, 2941 1090, 2941 9090, 2942 0090 के अधीन भी होते हैं। किसी भी प्रकार से सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जॉच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

### **समान वस्तु**

9. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसा आवेदकों ने बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ओ-एसिड और संबद्ध देश से आयातित ओ-एसिड भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए

नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

### शामिल देश

10. वर्तमान जाँच चीन जन. गण. (जिसे 'संबद्ध देश' भी कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन से संबंधित है।

### सामान्य मूल्य

11. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन के मामले में नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदकों ने भारत में उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करके चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य का दावा किया है। नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार यह माना जाता है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अधीन कार्य कर रहे हैं।

12. उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता और चीन जन. गण. में प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन. गण. के लिए संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार लगाया गया है।

### निर्यात कीमत

13. आवेदक द्वारा निर्यात कीमत को आईबीआईएस के सौदा-वार आयात आकड़ों से प्राप्त आकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़े, बैंक प्रभार और वैट के लिए समायोजन सहित कीमत संबंधी समायोजन किये गये हैं।

### पाटन मार्जिन

14. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से अधिक है, जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। इस प्रकार अनुमानित पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है।

### क्षति और कारणात्मक संबंध

15. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए नई सुविधा स्थापित की है और जाँच अवधि के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। आवेदक ने दावा किया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तव में बाधा हो रही है। आवेदक ने उस अवधि जिसमें उसका वाणिज्यिक उत्पादन था के लिए क्षति से संबंधित विभिन्न मापदंडों संबंधी सूचना प्रस्तुत की है। घरेलू उद्योग को उत्पादन शुरू करने से पहले परिकल्पित उचित कीमतों से वास्तविक रूप से कम कीमतों पर उत्पाद को बेचना पड़ रहा है। आवेदक ने इस प्रकार दावा किया है कि उसके वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के समय भी घरेलू उद्योग को बाजार में उसका स्थान नहीं मिला था।

16. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से वास्तविक क्षति हुई है जो समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में पाटित आयातों की बड़ी हुई मात्रा, भारी कीमत कटौती, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, निरंतर वित्तीय घाटे, निवेश पर आय, नकद प्रवाह, मालसूचियों आदि से स्पष्ट है। क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है और संबद्ध आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है। घरेलू उद्योग पर आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, यह नोट किया जाता

है कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ जैसे मापदंडों के संबंध में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को भारीवित्तीय घाटा, नकद घाटा और निवेश पर ऋणात्मक आय का सामना करना पड़ रहा है।

17. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

### पाटनरोधी जाँच की शुरूआत

18. पूर्वोक्त पैराग्राफों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरूआत करते हैं।

### जांच अवधि (पीओआई)

19. याचिकाकर्ता ने बताया है कि उन्होंने अपना परीक्षण उत्पादन जून 2015 में और पूरे पैमाने पर उत्पादन अक्टूबर 2015 में शुरू किया था। याचिकाकर्ता ने जुलाई 2015 से जून 2016 की अवधि के लिए आकड़ों के विश्लेषण के साथ याचिका प्रस्तुत की है। प्राधिकारी प्रस्तावित जाँच अवधि (पीओआई) के रूप में जुलाई 2015 – जून 2016 (12 महीने) निर्धारित करना उचित समझते हैं। किसी भी तरह से जहां तक क्षति विश्लेषण का संबंध है उसे मासिक आधार पर किए जाने का प्रस्ताव है।

### सूचना प्रस्तुत करना

20. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**  
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग**  
**चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,**  
**नई दिल्ली- 110001**

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

### समय-सीमा

22. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

#### **अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

24. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

25. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पाँच (5) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

26. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

27. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

28. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

29. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

30. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

#### **असहयोग**

31. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)**

New Delhi, the 21st September, 2016

**INITIATION NOTIFICATION****Subject: Anti Dumping investigation concerning imports of O-Acid originating in or exported from China PR.**

**No. 14/31/2016-DGAD.**— M/s. Aarti Drugs Ltd. (hereinafter referred to as the applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti dumping duty concerning imports of O- Acid (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China (hereinafter also referred to as the subject country).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

**Domestic Industry & Standing**

3. The petition has been filed by M/s. Aarti Drugs Ltd., Mumbai as a domestic producer of the product under consideration. There is no other known producer of product under consideration in India. Petitioner is the new producer of the product under consideration in India with no past history of production in India.

4. The petitioner has stated that they were importing O-Acid before they commenced production of O-Acid for consumption in production of the final product namely ofloxacin. After commencement of their own production of O-Acid, petitioner had stopped importing O-Acid completely. However, the exporters from China reduced the prices very significantly. The decline in the prices by the Chinese producers was so significant that the landed prices of the imported O-Acid was below normatted cost of production of the petitioner and hence domestic industry was forced to import O-Acid from China to continue the production of the final product Ofloxacin.

5. As per the evidence available on record, the production of the applicant accounts for a major proportion in the gross domestic production of the like article. The Authority, therefore, determines that the applicant constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

**Product under consideration**

6. The product under consideration in the present petition is Ofloxacin acid or O-acid. It is an off-white to white crystalline powder and is used as an intermediate for the manufacture of Ofloxacin, which is a synthetic chemotherapeutic antibiotic of the fluoroquinolone drug class considered to be a second-generation fluoroquinolone. Ofloxacin is a racemic mixture, which consists of 50% levofloxacin (the biologically active component) and 50% of its "mirror image" or enantiomer dextrofloxacin.

7. Ofloxacin Acid is used in production of Ofloxacin, which is used to treat certain infections including bronchitis, pneumonia, and infections of the skin, bladder, urinary tract, reproductive organs, and prostate. Ofloxacin is sold under a wide variety of brand names as well as generic drug equivalents, for oral and intravenous administration. Ofloxacin is also available for topical use, as eye drops and ear drops. It is on the WHO Model List of Essential Medicines, the most important medications needed in a basic health system. The PUC can be manufactured as per IP/BP/EP/USP pharmacopeia standards.

8. Product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The PUC has a specific HS code 2941 9030, however, the imports also take place under various other HS codes namely

2915 2990, 2916 3990, 2918 3090, 2918 9900, 2934 9900, 2941 1090, 2941 9090, 2942 0090. Customs classification in any case is indicative and not binding on the scope of the product under consideration in the present investigation.

### **Like Article**

9. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject country and that produced by the applicant. As submitted by the applicant, O-Acid produced by the domestic industry and imported from subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The applicant has further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicant in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

### **Country/(ies) involved**

10. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China (referred to as the subject country).

### **Normal Value**

11. Applicant has claimed that China should be treated as a non-market economy and normal value in case of China should be determined in accordance with para-7 and 8 of Annexure I of the Rules. The applicant has claimed normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non market economy conditions.

12. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from China PR, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

### **Export Price**

13. The applicant has determined export price on the basis of data procured from transaction wise IBIS import data. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight, bank charges, and adjustment for VAT to arrive at the net export price.

### **Dumping Margin**

14. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margin is estimated to be above de minimis.

### **Injury and Causal Link**

15. The applicant has set up a new facility for production of the product under consideration and commenced commercial production within the investigation period. The applicant has claimed that dumping of the product under consideration in India is materially retarding the establishment of the domestic industry. The applicant has furnished information on various parameters relating to injury for the period for which it has commercial production. The domestic industry is forced to sell the product at prices materially below the fair prices envisaged by the domestic industry before commencement of production. The applicant has thus claimed that even when its commercial production has begun, the domestic industry is yet to find its place in the market.

16. The applicant has claimed that domestic industry has suffered material injury from dumped imports exemplified by various parameters such as significant increase in imports in absolute terms as also relative to the production and consumption in India, significant price undercutting, capacity utilization market share, continued financial losses, return on investments, cash flow, inventories, etc. The demand for the product under consideration has increased over the injury period and subject imports have increased in absolute terms. The imports are undercutting the domestic prices. The imports have suppressed/depressed the domestic prices over the injury period. With regard to consequent impact of the imports on the domestic

industry, it is noted that performance of the domestic industry has deteriorated in respect of parameters such as profits; return on capital employed and cash profits. The domestic industry is suffering significant financial losses, cash losses and negative return on investments.

17. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

#### **Initiation of anti-dumping investigations**

18. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.

#### **Period of Investigation (POI)**

19. Petitioner has submitted that they started their trial production in June 2015 and full scale production from October 2015. The Petitioner has submitted petition with analysis of the data for the period July 2015 to June 2016. The Authority considers it appropriate to determine July 2015 - June 2016 (12 months) as the proposed POI. In any case, as far as injury analysis is concerned the same is proposed to be carried out on month to month basis.

#### **Submission of information**

20. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce  
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,  
New Delhi -110001.**

21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

#### **Time limit**

22. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

#### **Submission of Information on Non-Confidential basis**

24. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

25. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential



information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non confidential version must be submitted by all the interested parties.

26. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

27. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

28. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

29. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **Inspection of Public File**

30. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

#### **Non-cooperation**

31. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A.K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority